

न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी जसवन्त सिंह, आर.ए.एस.

अपील संख्या 31/2025 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2025/43)

काशीराम पुत्र मूलाराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड नं. 15 कस्बा
राजगढ तहसील राजगढ जिला चूरु।

अपीलान्ट

बनाम

1. लाल मोहम्मद पुत्र सारू खां जाति दमामी निवासी मौहल्ला दमामियान
कस्बा राजगढ तहसील राजगढ जिला चूरु।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार एवं उप पंजीयक राजगढ जिला
चूरु।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थित: 1. श्री रतनलाल प्रजापत - अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री राजेश वैद - अभिभाषक रेस्पोडेंट सं. 1

निर्णय

दिनांक: 29.07.2025

1. यह अपील भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत
उपखण्ड अधिकारी राजगढ के प्रार्थना पत्र संख्या 615/2023
निर्णय दिनांक 06.05.2024 के विरुद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 लाल
मोहम्मद ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ में
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम
पेश कर विवादित कृषि भूमि खसरा नं. 2922/1698 तादादी 1.4175
हैक्टेयर रोही कस्बा राजगढ की अनुभवी पटवारी गिरदावर की टीम
गठित कर पैमाइश करवाई जाकर चारों तरफ की सीमाओ की
पत्थर गढी करने के आदेश जारी करवाये जाने का निवेदन किया।
जिस पर उपखण्ड अधिकारी राजगढ ने अपने निर्णय दिनांक
06.05.2024 द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित कृषि भूमि
खसरा नं. 2922/1698 तादादी 1.4175 हैक्टेयर रोही कस्बा राजगढ
की चारो सीमाओ का सीमाज्ञान करवाने हेतु योग्य पटवारियो की
टीम तैयार की जाकर सीमाज्ञान कराया जाकर पुख्ता सीमाचिन्ह
कायम किये जाने व पत्थरगढी करने के आदेश दिये। उक्त आदेश
के विरुद्ध अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

1910-
अतिरिक्त सहायक आयुक्त
बीकानेर



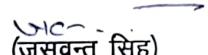
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।
4. अपीलान्त के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो में अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुवे बहस के दौरान कहा कि रेस्पोंडेंट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ में प्रार्थना पत्र पेश कर कृषि भूमि खसरा नं. 2922/1698 तादादी 1.4175 हैक्टेयर रोही कस्बा राजगढ़ की पत्थरगढी व सीमा ज्ञान करवाने बाबत पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र में रेस्पोंडेंट सं. 1 ने तथ्यों को छुपाते हुए अपीलान्त को पक्षकार नहीं बनाया और मातहत न्यायालय को मुगालते में रखते हुए उक्त आदेश प्राप्त किया है। वास्तविक तथ्य यह है कि विवादित खसरा सं. 2922/1698 के गत खसरा सं. 1698 कुल तादादी 5.67 हैक्टेयर वाके रोही कस्बा राजगढ़ रहा है जो पूर्व में संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि रही है लेकिन उक्त खसरा का खाता विभाजन होकर खसरा सं. 2922/1698 बना है जिसको लेकर लाल मोहम्मद द्वारा सीमा ज्ञान व पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र बिना अपीलान्त को पक्षकार बनाये केवल राजस्थान सरकार के खिलाफ सोची समझी साजिस के तहत पेश किया है। उक्त खाता विभाजन के निर्णय के खिलाफ एक अपील राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर पदेन भू प्रबन्ध अधिकारी कैम्प कोर्ट चूरु में विचाराधीन है। जिसका निर्णय अभी नहीं हुआ है। इन तथ्यों को छुपाते हुए रेस्पोंडेंट द्वारा मातहत न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया गया। रेस्पोंडेंट सं. 1 चालक व राजनीतिक पहुच वाला व्यक्ति है जो उक्त सीमाज्ञान व पत्थरगढी के आदेश की आड में अपीलान्त की भूमि हडपने की मंशा रखता है। अधीनस्थ न्यायालय न पटवारी की रिपोर्ट भी नहीं मंगवाई और मनमाने तरीके से निर्णय जारी कर अहम कानूनी भूल की है। अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी अपने अधिवक्ता के पास जाकर नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन पेश किया जो नकले बाद तैयारी दिनांक 13.05.2024 को प्राप्त हुई। जानकारी से अपील अन्दर नियाद पेश की गई है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.05.2024 को अपास्त किया जाकर विवादित खाता विभाजन से पूर्व खातेदार रहे

व्यक्तियों को आवश्यक पक्षकार कायम किया जाकर सुनवाई का अवसर दिया जाकर गुणावगुण पर पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड अदालत उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला चूरु को किया जावे।

5. रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के निर्णय दिनांक 06.05.2024 के विरुद्ध अपीलान्ट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है। अपीलान्ट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने से पूर्व न्यायालय से परमीशन भी नहीं ली और ना ही अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी प्रस्तुत किया। अपीलान्ट को अपील पेश करने की LOCUS STANDI नहीं है। इसलिए अपीलान्ट की अपील LOCUS STANDI के अभाव में खारिज की जावे। साथ ही उन्होंने कथन किया कि रेस्पोंडेन्ट सं. 1 अपने खेत खसरा नम्बर की पत्थरगढ़ी करवा रहा है, इसमें अपीलान्ट को क्या दुविधा है। रेस्पोंडेन्ट अपनी सीमाओं की पत्थरगढ़ी चाहता है। जिस पर कोई स्थगन आदेश नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय सही है अपीलान्ट की अपील सारहीन हो चुकी है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।
6. हमने विद्वान अभिभाषकगणों की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। प्रस्तुत अपील उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के निर्णय दिनांक 06.05.2024 के विरुद्ध पेश की गई है जिसमें रेस्पोंडेन्ट लाल मोहम्मद का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित कृषि भूमि खसरा नं. 2922/1698 तादादी 1.4175 हैक्टेयर रोही कस्बा राजगढ़ की चारों सीमाओं का सीमाज्ञान करवाने हेतु योग्य पटवारियों की टीम तैयार की जाकर सीमाज्ञान कराया जाकर पुख्ता सीमाचिन्ह कायम किये जाने व पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिया गया है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था, इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने के लिए न्यायालय की परमीशन बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी प्रस्तुत भी नहीं किया है। साथ ही यदि पक्षकारों के मध्य अगर सीमा विवाद है तो वे अपनी खातेदारी भूमि की सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी करवाने का

अधीनस्थ न्यायालय
राजगढ़

कानूनी हक है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.05.2024 में हस्तक्षेप की गुजाईश प्रतीत नहीं होती है। लिहाजा अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.05.2024 को यथावत रखा जाता है। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 29.07.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(जसवन्त सिंह)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर